इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कई तरह की भाषाएं वहां पर हैं, जिनमें ब्रोडकास्ट होता है और इस बात को देखते हुए क्या आप एक रेडियो स्टेशन और राजस्थान में खोलेंगे क्योंकि वह देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान से वहां पर बार बार लड़ाई होती रहती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए और इस बात को देखते हुए कि वह भाग बहुत पिछड़ा हुआ है, क्या आप और अधिक स्टेशन वहां पर खोलेंगे। दूसरी बात यह है कि वहां पर रेडियो स्टेशनों पर और अधिक कार्यक्रम चलाए जाएं और टी०वी० पर स्वतंत्र न्यूज प्रसारित करने की वहां पर छूट दी जाए, क्या आप ऐसा करेंगे।

MR. SPEAKER: The question does not arise.

श्री हरिकिनाथ तिवारी : मंत्री जी ने कहा कि जिन स्थानों पर एक से अधिक प्रान्तों को या अधिक पापुलेशन को सर्व करना पड़ता है, वहां सीनियर आफिसर दिये जाते हैं और जहां कम लोगों को सर्व करना पड़ता है, वहां जूनियर आफिसर को लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीनगर या चंडीगढ़ में, इन दोनों को मिला दिया जाए या दो, चार को और मिला दिया जाए, तो भी ये यू०पी० से कम होंगे, बिहार से कम होंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जूनियर आफिसर क्यों भेजे गये और सीनियर आफिसर क्यों नहीं भेजे गये और जूनियर और सीनियर आफिसर्स को पोस्ट करने का आप का क्या क्राइटीरिया है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न जो है, यह तो केवल न्यूज यूनिट के बारे में है, रीजनल न्यूज के बारे में है और रीजनल बुलेटिन्स के बारे में है। जहां तक स्टेशन्स का सवाल है, उन में अधिकारी बहुत ऊंचे लेविल के हैं जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, तो वहां पर रीजनल बुलेटिन्स दो ही प्रसारित होते हैं जबकि श्रीनगर में 8 बुलेटिन्स प्रसारित होते हैं काश्मीरी में और उर्दू में और इसीलिए वहां पर जो इसके लिए अधिकारी है वह ऊंचे लेविल का है लेकिन मैं स्वयं चाहता हूं कि अनेक स्थानों पर विशेषकर स्टेट्स की कैपिटल्स में जैसे लखनऊ में या जयपुर में, अप-ग्रेडेशन की जरूरत मैं अनुभव करता हूं। लेकिन कुछ कारण हैं जिन से अभी यह नहीं हो सकता और जब तक वे कारण हैं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता।

श्री राम कंवर बरेव : यह प्रश्न सीनियर और जूनियर आफिसर्स का समाचार प्रसारण के मामले में पूछा गया है, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां सीनियर आफिसर्स होते हैं और जहां जूनियर आफिसर्स होते हैं, जो समाचार प्रसारण का कार्य करते हैं, उन में क्या अन्तर है। और सीनियर और जूनियर आफिसर्स को पोस्ट करने का मापदंड क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं पहले ही प्रमुख प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि किसी स्थान पर न्यूज एडीटर और असिसटेंट एडीटर कितने हों, इसकी कसौटी यह है कि वहां से कितने बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं और वे कितने क्षेत्रों और राज्यों को सर्व करते हैं। फिर यह भी देखा जाता है कि कोई स्ट्रेटिजिक फैक्टर तो नहीं है। मैंने ये सब बातें गिनायी है और उन्हीं के आधार पर निर्णय होता है।

श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन' : मंत्री महोदय ने बताया हैं कि यू० पी० में दो भाषाओं में बुलेटिन प्रसारित होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जब मैथिली भोजपुरी, मगही, उर्दू, हिन्दी सभी विभिन्न भाषाएं हैं तो वहां फिर जूनियर आफिसर रखने का क्या कारण है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पटना से हिन्दी और दो क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं।

Demand of Iron and Steel in M. P.

+

*849. DR. VASANT KUMAR PANDIT:

SHRI DAYA RAM SHAKYA:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what was the total requirement of iron and steel in Madhya Pradesh for the years 1977-78 and how much quantity was actually granted for the two years; the reasons for the short supply; and

(b) whether Government of Madhya Pradesh have requested the Government of India to open a Steel Stockyard at Jabalpur?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) State-wise figures of requirement of iron and steel are not maintained. However, despatches of iron and steel to Madhya Pradesh from the steel plants in the public sector, including supplies to the Madhya Pradesh Laghu

Udyog Nigam, during 1977-78 and 1978-79 were as follows:—

('000 tonnes)

Category	1977-78	1978-78 (Provisional)
Pig Iron	41	59
Saleable Steel	208	225

(b) Yes, Sir,

DR. VASANT KUMAR PANDIT: The first sentence of this reply bears repetition "State-wise figures of requirement of iron and steel are not maintained". This gives a clue of all the *golmal* and *garbar* in the supply of Iron and steel. I would like to know....

(Interruptions)

SHRI RAGHAVJI: When the information is not available, the question should be postponed.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: What sort of method do they adopt? What is the criteria? What are the norms? If they do not maintain the figures of requirements of the States, how is the allocation made to the States? Is it on an *ad hoc* basis? Is it on whimsical basis? It is said there is some method in madness also. Is allocation by the Iron and Steel Deptt. made on madness basis? There must be some method. On what method is allocation made if you do not maintain state requirements. Becuase Madhya Pradesh requires more than 3 lakh metric tonnes of iron and steel? Madhya Pradesh Government has constantly made its requirement known to the Central Government. There are about 5,000 Industrial units registered.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: You are making a speech. Please put the question.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: He says that data is not available. On what basis allocations are made to the States?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: He wants to know what is the method of madness!

SHRI BIJU PATNAIK: The method of madness arises from the fact that no State Government, and I repeat, no State Government makes a collective demand on the Steel Authority of India. It had never been done. It has not been done till today. We do not maintain the so called state-wise figures. The demands are made by the consumers—whether it is in public sector, Defence, other consumers, wagon builders or whatever it is. They make the demands and the demands are met by the Steel Authority of India and also by the Tata Iron and Steel and also by mini-steel plants and the rolling mills of which we have got about 700 and odd in this country. They supply according to the requirement of different consumers in different States. What the public sector steel plants have supplied to Madhya Pradesh, is the figure that I have given to the hon. member.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: In reply to my question (b), the hon. Minister has said 'yes' only. I would like to know whether the establishment of stockyard at Jabalpur which is a central place, which can serve 17 districts of Vindhyachal and Mahakoshal, is being made?

MR. SPEAKER: This question had come up last month.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: My question is on Madhya Pradesh. Whether the Government is going to take a decision on that? Otherwise, there is a proposal pending with the Centre from the Government of Madhya Pradesh for establishing a pelletisation factory in Bastar District where lot of raw material is lying idle. Therefore, I would like to know from the Government; what decisions

have been taken with regard to opening a stock-yard in Jabalpur and/or what is the decision with regard to establishing a pelletisation factory at that place?

SHRI BIJU PATNAIK: How does it arise from part (b) of the question? (*Interruptions*) The hon. Member knows that there is already a large steel plant in Bhilai in Madhya Pradesh. And Madhya Pradesh has three stockyards at Bhilai, Indore, and Gwalior. The question of opening another stockyard as he wanted in Jabalpur, is receiving our attention.

श्री० हरीराम मक्कासर गोदारा : आज देश में लोहे की कीमतें आसमान को छू रही हैं । नीचे आने के बजाय ये ऊंची जा रही हैं इसका क्या कारण है और इनको नीचे लाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल है ।

श्री राघवजी : क्या कभी आपने एसेसमेंट किया है कि मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कितने स्टील की आवश्यकता प्रति मास रहती है और कितने स्टील की पूर्ति आप करते हैं ? मध्य प्रदेश सरकार बार बार कह रही है कि इन यूनिट्स की आवश्यकतायें अधिक हैं और पूर्ति कम हो रही है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि ये जो इकाइयां हैं ये ठीक से नहीं चल पा रही है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जबलपुर में स्टाकयार्ड खोलने का प्रस्ताव आपको कब प्राप्त हुआ था और अभी तक उस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया है ?

SHRI BIJU PATNAIK: I have answered this question about Jabalpur so many times. When the Steel Authority of India are convinced that there is a sufficient offtake from the stockyards...

MR. SPEAKER: Only last week, this question had come up.

SHRI RAGHAVJI: I want to know what is the demand of the industrial units of Madhya Pradesh and what they are supplying?

SHRI BIJU PATNAIK: Again, I do not know the demand. There is no such thing as demand from Madhya Pradesh. But we have supplied to the Laghu Udyog Nigam only 1400 tonnes in 1977-78 and in 1978-79, we have supplied to them 7000 tonnes. There is no demand of steel from Laghu Udyog Nigam.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मूल प्रश्न में यह पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की आवश्यकता कितने स्टील की है । इसका उत्तर मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में नहीं दिया है । इसको छिपाया गया है । इसके आंकड़े नहीं बताए गए ह ।

MR. SPEAKER: If you are so loud, my ear-drums will go off.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मध्य प्रदेश को स्टील न मिलने के कारण सवा तीन सौ लघु उद्योग वहां बन्द पड़े हैं । इन लघु उद्योगों को सरकारी आर्डर भी मिले हुए हैं लेकिन उनकी भी पूर्ति ये नहीं कर पा रहे हैं । इस कारण से मध्य प्रदेश का विकास रुका हुआ है मात्र स्टील न मिलने की वजह से ।

अध्यक्ष महोदय : भाषण न दें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : भाषण कहां दे रहा हूं । मंत्री महोदय बहुत होशियार हैं । लोहे के धपले के जो मामले हैं उनकी वजह से ये खिन्न हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की लोहे की जो आवश्यकता है और जिसके न मिलने के कारण वहां का विकास रुका हुआ है और वहां के लघु उद्योग बन्द पड़े हैं वे फिर से चालू हो सकें, इसके वास्ते क्या उसकी लोहे की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी ?

SHRI BIJU PATNAIK: About the Laghu Udyog Nigam i.e. the Small Scale Industries Corporation of Madhya Pradesh, whatever the demands are, they are being met.

SHRI RAGHAVJI: He is not asking about the Nigam but about the Madhya Pradesh laghu udyog?

SHRI BIJU PATNAIK: Perhaps, the hon. Member does not know that all the small scale industries of a State make their demands on the Small Scale Industries Corporation.

The Government or the Steel Authority of India make supplies only to the Small-scale Industries Corporation who in turn distribute it to the small-scale industries. And what the hond. Member Mr. Kachwai said is that 340 small-scale industries are closed. I am sure he has not gone round and seen even one which is closed. Let him bring it to my notice.

(*Interruptions*)

SHRI V. DHANDAYUTHAPANI: Sir, the price of steel is very high. So, the Government has allowed the import of smelting scraps to overcome the shortage of the raw materials. Accordginly, the Government has already allowed the import of smelting scraps. So, I would like to know from the Minister whether there is any proposal to overcome the shortage of raw materials and whether the scraps can be imported from other countries.

MR. SPEAKER: It does not arise.

SHRI BIJU PATNAIK: It does not arise. But I can assure the hon. Member...

MR. SPEAKER: Question No. 850.

Rural Electrification Schemes for Purnea District of Bihar

*850. SHRI HALIMUDDIN AHMED: Will the Minister of ENERGY be pleased to lay a statement showing:

(a) the rural electrification schemes of Purnea district in Bihar received by the Rural Electrification Corporation during 1977-78 and 1978-79 for approval;

(b) the number of villages proposed to be electrified under each scheme with full particulars;

(c) the progress made in respect of each scheme so far; and

(d) the reason for the delay in according approval to the schemes pending till now?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) to (d). A statement is laid on the table of the House.

Statement

RURAL ELECTRIFICATION SCHEMES FOR PURNEA DISTRICT OF BIHAR

(a) 7 Rural Electrification schemes of Purnea District in Bihar were received by the Rural Electrification Corporation from Bihar State Electricity Board during 1977-78 and 1978-79. These included 2 schemes which were orginally received in 1976-77 but were referred back to the Board for revision and had been resubmitted by them duly revised.

(b) The details of the schemes including the number of villages to be electrified under each of them, are given in Annexure I.

(c) 4 schemes have been sanctioned by the Corporation. One was withdrawn by the Board. The remaining two schemes are pending examination with the Corporation.

The schemes sanctioned by the Corporation are phased for completion over a period ranging upto 5 years and are in initial stages of implementation.

(d) The two schemes pending with the Corporation were received in December, 1978 and January, 1979. These will be considered for sanction of loan assistance during 1979-80, if on examination they are found to be technically feasible and financially viable, subject to the availability of funds.